www.railsamacharbureau.com

सम्पूर्ण भारतीय रेल जगत का प्रथम पाक्षिक, प्रयागराज से प्रकाशित

रेल समाचार ब्यूरो

सन् 1990 से रेल सेवा में समर्पित

"विरासत को संजोकर, आधुनिकता की राह पर बढ़ती भारतीय रेल। हर नई पहल के साथ, देश के भविष्य को देती नई गति।"

"हर पटरी पर प्रगति की रफ्तार, हर सफर में विश्वास की पहचान। भारतीय रेलकृनए भारत की धड़कन, हर दिल का अभिमान।"

वर्ष-36 अंक:14 रेल समाचार ब्यूरो प्रयागराज 16 जुलाई - 31 जुलाई 2026 पृष्ठ 08, मूल्य:20 रु. मात्र. डाक खर्च (रंगीन सहित)

विकसित भारत की ओर रफ्तार तेज़

बुलेट ट्रेन से बदलेगा भारत का रेल भविष्य

सूत्र - रे.स.ब्यू - भारत की बहुप्रतीक्षित बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण प्रगति की जानकारी साझा की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का पहला परिचालन खंड वर्ष 2027 में यात्रियों के लिए शुरू किया जाएगा। परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि देश में हाई-स्पीड रेल सेवा का लाभ जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जा सके।

रेल मंत्री के अनुसार, परियोजना का पहला सेक्शन गुजरात के सूरत और बिलीमोरा के बीच संचालित होगा। इस हिस्से में निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसे सबसे पहले परिचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि हाई-स्पीड रेल सेवा का पहला अनुभव निर्धारित समयसीमा के भीतर यात्रियों तक पहुंचे।

मुंबई अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के पूर्ण रूप से चालू होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। वर्तमान में लगभग सात घंटे में पूरी होने वाली यात्रा घटकर करीब दो से तीन घंटे रह जाएगी, जिससे यात्रियों को तेज, सुविधाजनक और समय की बचत करने वाली परिवहन सुविधा मिलेगी।

इस परियोजना के तहत संचालित होने वाली बुलेट ट्रेन की अधिकतम गति लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके साथ ही यह देश की सबसे तेज रेल सेवा बन जाएगी और भारतीय रेलवे के आधुनिक परिवहन ढांचे में एक नया अध्याय जोड़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना केवल तेज यात्रा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई गति दे सकती है। इसके माध्यम से निर्माण और इंजीनियरिंग गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही औद्योगिक कॉरिडोर, व्यापार और निवेश को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

मुंबई अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना को भारत की आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो भविष्य में देश में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार की आधारशिला भी बन सकती है।

मुख्य बिंदु

- 2027 में शुरू होगा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला परिचालन खंड।
- सूरत बिलीमोरा सेक्शन से होगी हाई-स्पीड रेल सेवा की शुरुआत।
- बुलेट ट्रेन की अधिकतम गति 320 किमी प्रति घंटा होगी।
- मुंबई अहमदाबाद यात्रा समय लगभग 7 घंटे से घटकर 2–3 घंटे रह जाएगा।
- परियोजना से रोजगार, उद्योग, निवेश और क्षेत्रीय विकास को मिलेगा बड़ा बल।

रेल यात्रा में हाइड्रोजन युग की दस्तक

सूत्र - रे.स.ब्यू - भारतीय रेलवे जल्द ही स्वच्छ और आधुनिक रेल तकनीक की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच संचालित की जाएगी। लगभग 89 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर ट्रेन प्रतिदिन दो राउंड ट्रिप करेगी और कुल मिलाकर करीब 356 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ट्रेन में 682 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि खड़े होकर यात्रा करने वाले यात्रियों सहित इसकी कुल क्षमता लगभग 2,600 यात्रियों की होगी। यह सेवा विशेष रूप से रोजाना यात्रा करने वाले कर्मचारियों, छात्रों और स्थानीय यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

12 स्टेशनों पर मिलेगा ठहराव

हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन 74010/74009 नंबर से किया जाएगा। जींद और सोनीपत के बीच यह ट्रेन जींद सिटी, पांडू पिंडारा, ललित खेड़ा, भांबेवा, इशापुर खेड़ी, बुटाना, खंडराई, गोहाना, रबड़ा, लाठ मोहन हरियाणा और बरवासनी सहित कुल 12 स्टेशनों पर रुकेगी। यह पूरा रेलखंड उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के अंतर्गत आता है।

ऐसे काम करेगी हाइड्रोजन तकनीक

यह ट्रेन 1,200 किलोवाट-आवर क्षमता वाले हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम से संचालित होगी। इसमें संग्रहित हाइड्रोजन फ्यूल सेल के भीतर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर बिजली उत्पन्न करेगा, जिससे ट्रेन के मोटर संचालित होंगे। इस प्रक्रिया का एकमात्र उत्सर्जन जलवाष्प होगा, इसलिए इसे लगभग कार्बन-फ्री तकनीक माना जा रहा है। परीक्षण के दौरान ट्रेन ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल की थी। हालांकि नियमित यात्री सेवा में सुरक्षा और परिचालन दक्षता को ध्यान में रखते हुए इसकी गति लगभग 75 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाएगी। यह तकनीक विशेष रूप से उन रेल मार्गों के लिए उपयोगी मानी जा रही है, जहां अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है।

111.83 करोड़ रुपये की परियोजना

भारतीय रेलवे ने इस परियोजना के लिए 111.83 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस राशि में मौजूदा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (DEMU) को हाइड्रोजन ट्रेन में परिवर्तित करने के साथ-साथ हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण, रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और आवश्यक सुरक्षा प्रणालियों की स्थापना भी शामिल है।

सुरक्षा पर विशेष जोर

हाइड्रोजन की ज्वलनशील प्रकृति को देखते हुए ट्रेन में लीक डिटेक्टर, फायर डिटेक्शन सिस्टम और लगातार सुरक्षा निगरानी जैसी उन्नत व्यवस्थाएं की गई हैं। आधुनिक सेंसर किसी भी संभावित रिसाव का तुरंत पता लगाकर स्वचालित सुरक्षा प्रणाली सक्रिय कर देंगे। चूंकि हाइड्रोजन हवा से हल्की गैस है, इसलिए रिसाव की स्थिति में यह तेजी से वातावरण में फैल जाती है, जिससे आग लगने का जोखिम काफी कम हो जाता है।

स्वच्छ रेल तकनीक की दिशा में अहम कदम

इस परियोजना के साथ भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो रहा है, जो हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक पर काम कर रहे हैं। यदि जींद सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना सफल रहती है, तो भविष्य में देश के अन्य गैर-विद्युतीकृत रेल मार्गों पर भी इस तकनीक के उपयोग का रास्ता खुल सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए अतिरिक्त होमिंग सुविधाएं बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी।

अवसंरचना संवर्धन की यह पहल मौजूदा परिसंपत्तियों को अनुकूलित करने, बेड़े का विस्तार करने और रखरखाव क्षमता को बढ़ाने के लिए है

सूत्र - रे.स.ब्यू - भारतीय रेलवे ने लोकोमोटिव रखरखाव अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) के अंतर्गत रायपुर स्थित हाई हॉर्स पावर (एचएचपी) डीजल शेड में 250 थ्री फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए अतिरिक्त होमिंग सुविधाएं बनाने के उद्देश्य से 175 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है।

होमिंग का तात्पर्य किसी लोकोमोटिव को एक निर्दिष्ट लोकोमोटिव शेड में जगह देने से है, जो उसके प्राथमिक रखरखाव केंद्र के रूप में कार्य करता है। होमिंग शेड की सुविधा लोकोमोटिव के निर्धारित रखरखाव, सुरक्षा निरीक्षण, मरम्मत और समग्र देखभाल के लिए होती है ताकि उसका सुरक्षित और कुशल संचालन सुनिश्चित हो सके।

यह परियोजना भारतीय रेलवे द्वारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बेड़े के तेजी से विस्तार और पूरे नेटवर्क में माल ढुलाई तथा यात्री परिचालन में वृद्धि के अनुरूप रखरखाव बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की दिशा में चल रहे प्रयासों के तहत स्वीकृत की गई है।

इन अतिरिक्त होमिंग सुविधाओं से भारतीय रेलवे को रायपुर डिपो में मौजूदा बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी, साथ ही भविष्य में तकनीकी विस्तार के लिए आवश्यक स्थान भी उपलब्ध होगा।

रेलवे ने उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए 206 करोड़ रुपये की लागत से कवच को मंजूरी दी

रेलगाड़ियों के सुरक्षित, तेज और अधिक विश्वसनीय संचालन के लिए रेवाड़ी–दिल्ली और शकूरबस्ती–बठिंडा खंडों के साथ–साथ फीडर शाखा लाइनों पर भी कवच 4.0 की शुरुआत की जाएगी

सूत्र - रे.स.ब्यू - रेलवे ने स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, उत्तरी रेलवे के दिल्ली खंड के रेवाड़ी-दिल्ली और शकूरबस्ती-बठिंडा खंडों के 680 किलोमीटर (आरकेएम) पर कवच संस्करण 4.0 मंजूरी दे दी है। इसमें फीडर शाखा लाइनें भी शामिल हैं। इस परियोजना को 206 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई है।

यह परियोजना रेलवे द्वारा देशव्यापी स्तर पर चलाए जा रहे कवच कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका उद्देश्य उच्च घनत्व वाले और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है।

स्वदेशी रूप से विकसित कवच प्रणाली को खतरे के संकेत पार करने (एसपीएडी) की घटनाओं और रेल दुर्घटनाओं को रोककर रेलवे सुरक्षा को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली रेलगाडियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखती है, आवश्यकता पड़ने पर स्वचालित रूप से ब्रेक लगाती है और अधिकतम अनुमत गति तथा घने कोहरे जैसी मौसम की प्रतिकूल स्थितियों में भी रेलगाडियों का संचालन सुनिश्चित करती है।

रेलवे के इन महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच संस्करण 4.0 की शुरूआत से सुरक्षा मजबूत होगी, परिचालन दक्षता में सुधार होगा, रेलगाडियों के संचालन की विश्वसनीयता बढ़ेगी और यात्री और माल ढुलाई दोनों सेवाओं में तेजी आएगी तथा प्रौद्योगिकी-संचालित आवाजाही को समर्थन मिलेगा।

रेलवे संरक्षा को और मजबूत बनाने पर मंथन, रेलवे बोर्ड में हुई उच्चस्तरीय बैठक

सूत्र - रे.स.ब्यू - नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड के प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस में भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों के प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारियों (PCSO) के साथ संरक्षा संबंधी विषयों पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। बैठक में रेलवे बोर्ड के महानिदेशक (सेफ्टी/संरक्षा) श्री हितेंद्र मल्होत्रा की उपस्थिति में रेलवे संरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।

सम्मेलन के दौरान संरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने, विभिन्न जोनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा संरक्षा से संबंधित कार्यों की समीक्षा पर विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों ने विभिन्न जोनों में लागू संरक्षा उपायों, कार्यप्रणालियों और अनुभवों पर भी चर्चा की तथा संरक्षा मानकों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया।

बैठक में संरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा करते हुए भविष्य की कार्ययोजना, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाने और विभिन्न जोनों के बीच समन्वय को और मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही, सुरक्षित रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी, सतत समीक्षा और आवश्यक सुधारात्मक उपायों के महत्व पर भी बल दिया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय रेलवे की संरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना, विभिन्न जोनों के बीच बेहतर संवाद एवं समन्वय स्थापित करना तथा संरक्षा से जुड़े विषयों पर साझा दृष्टिकोण विकसित करना रहा।

भारतीय रेल ने राउरकेला-बोंडामुंडा खंड पर सुचारु यातायात के लिए बोंडामुंडा में 135 करोड़ रुपये की रेल फ्लाईओवर परियोजना को मंजूरी दी

4.59 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर माल ढुलाई और यात्रियों के आवागमन को अलग करेगा, क्षमता बढ़ाएगा और प्रति वर्ष अतिरिक्त 8 मिलियन टन माल ढुलाई को सक्षम करेगा

सूत्र - रे.स.ब्यू - भारतीय रेल ने माल ढुलाई क्षमता और परिचालन दक्षता को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए, दक्षिण पूर्वी रेल में बोंडामुंडा 'ए' केबिन से बोंडामुंडा लिंक 'बी' केबिन तक 4.59 किलोमीटर लंबे रेल फ्लाई ओवर के निर्माण को 135 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दे दी है।

इस परियोजना का उद्देश्य राउरकेला-बोंडामुंडा के महत्वपूर्ण खंड पर भीड़भाड़ को कम करना है, जो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारा है तथा खनन और इस्पात उत्पादन की गतिविधियों के विस्तार के कारण माल ढुलाई यातायात में तेजी से वृद्धि करने की सख्त आवश्यकता है।

एक महत्वपूर्ण औद्योगिक गलियारे पर क्षमता वृद्धि

एसएआईएल के बारसुआ-ताल्डीह-काल्टा खनन परिसर के विस्तार, राउरकेला स्टील प्लांट में बढ़े हुए उत्पादन और इस उच्च-घनत्व नेटवर्क (एचडीएन) मार्ग को दोगुना करने की योजना के कारण राउरकेला-बोंडामुंडा खंड में माल ढुलाई में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है।

रेल यातायात में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए, भारतीय रेल ने नए रेल फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जो यात्रियों और मालगाड़ियों के बीच क्रॉसिंग संबंधी टकराव को कम करते हुए ट्रेनों की निर्बाध आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगा।

बोंडामुंडा यार्ड में भीड़ कम करना और माल ढुलाई दक्षता में सुधार करना

प्रस्तावित फ्लाईओवर भारी मालगाड़ियों को यात्री ट्रेनों से अलग करेगा, जिससे बोंडामुंडा यार्ड में भीड़भाड़ काफी कम हो जाएगी। इस अलगाव से देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक माल ढुलाई गलियारों में से एक पर लाइन की क्षमता, परिचालन दक्षता, ट्रेनों की विश्वसनीयता और समग्र नेटवर्क प्रदर्शन में सुधार होगा।

परियोजना के चालू होने पर, इससे प्रति वर्ष अतिरिक्त 8 मिलियन टन (एमटीपीए) माल ढुलाई यातायात को संभालने में सुविधा होने की उम्मीद है, जिससे खनिजों और औद्योगिक उत्पादों की निकासी मजबूत होगी और माल परिवहन में भविष्य की वृद्धि को समर्थन मिलेगा।

इस परियोजना को भारतीय रेल के ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर के तहत चिन्हित किया गया है, जो देश भर में औद्योगिक विकास, माल ढुलाई में तेजी लाने और रसद दक्षता बढ़ाने के लिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में राष्ट्रीय उद्देश्य को बल देता है।

मालदा डिवीजन में सिग्नलिंग आधुनिक बनाने के लिए 20 स्थानों पर 274 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग परियोजना को स्वीकृति।

यह पूर्वी रेलवे के व्यस्ततम गलियारों में से एक पर सिग्नलिंग प्रणाली की विश्वसनीयता, दक्षता और रखरखाव क्षमता बढ़ाने की आधुनिकीकरण परियोजना है

सूत्र - रे.स.ब्यू - भारतीय रेल ने रेलवे सुरक्षा सुदृढ़ बनाने और सिग्नलिंग अवसंरचना के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पूर्वी रेलवे के मालदा डिवीजन (मंडल) में 20 स्थानों पर रिले-आधारित इंटरलॉकिंग को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलने की 274 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है।

इस परियोजना के तहत पूर्वी रेलवे के उच्च यातायात मार्ग पर स्थित 18 रेलवे स्टेशनों और 2 इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग (आईबीएस) स्थानों पर मौजूदा रिले रूम/पैनल इंटरलॉकिंग (पीआई/आरआरआई) प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) प्रणाली से बदला जाएगा। यह कंप्यूटर-आधारित उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली सिग्नल, ट्रैक और स्विच को आपस में इस तरह जोड़ती है कि जब तक आगे का रास्ता पूरी तरह साफ और सुरक्षित न हो, तब तक किसी ट्रेन को आगे बढ़ने का सिग्नल नहीं मिलता।

उच्च आवागमन मार्ग पर सिग्नलिंग अवसंरचना का आधुनिकीकरण

स्वीकृत परियोजना में मालदा डिवीजन में 18 स्टेशनों और 2 आईबीएस स्थानों सहित 20 परिचालन स्थानों पर पारंपरिक रिले-आधारित सिग्नलिंग प्रणाली को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग तकनीक से बदला जाएगा।

इस आधुनिकीकरण से सिग्नलिंग प्रणाली की विश्वसनीयता, दक्षता और रखरखाव क्षमता में काफी सुधार होगा, साथ ही यह पूर्वी रेलवे के सबसे व्यस्त रेल परिचालन गलियारों में से एक पर बढ़ते यात्री और माल यातायात के संचालन का मजबूत तकनीकी आधार तैयार करेगा।

अधिक सुरक्षित, स्मार्ट और विश्वसनीय ट्रेन संचालन

इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग उन्नत, त्रुटि-रहित सिग्नलिंग तकनीक है जो रूट सेटिंग और सिग्नलिंग कार्यों को स्वचालित करती है, साथ ही उपकरण की खराबी और मानवीय त्रुटियों की संभावना काफी कम कर देती है। उन्नत प्रणाली परिचालन स्थिति अनुरूपण को बढ़ाएगी, सेवा में व्यवधान में कमी लाएगी, गड़बड़ी के बाद सेवा बहाली त्वरित बनाएगी और समयबद्धता बढ़ाएगी।

यह परियोजना ट्रेन सुरक्षा मजबूत करने के साथ ही, परिचालन दक्षता में सुधार लाएगी और उच्च यातायात वाले मार्गों पर तेज और अधिक विश्वसनीय रेल आवागमन को बढ़ावा देगी। साथ ही यह कवच और अन्य आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिए बेहतर आधार तैयार करेगी।

इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग परियोजना को स्वीकृति भारतीय रेलवे के उस निरंतर अभियान का हिस्सा है जिसके तहत उन्नत प्रौद्योगिकियों द्वारा राष्ट्रीय नेटवर्क में सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिससे सुरक्षित, स्मार्ट और अधिक कुशल रेलवे संचालन सुनिश्चित हो।

भारतीय रेल ने जून 2026 में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में माल ढुलाई में 4 प्रतिशत और यात्री यातायात में स्थिर वृद्धि दर्ज की

सूत्र - रे.स.ब्यू - भारतीय रेल ने जून 2026 के दौरान मजबूत परिचालन प्रदर्शन जारी रखते हुए माल ढुलाई और यात्री सेवाओं दोनों में स्थिर वृद्धि दर्ज की है। माल परिवहन और यात्री यातायात में बढ़ोतरी तथा यात्री सेवाओं में निरंतर सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, प्रचालन तंत्र सुदृढ़ बनाने और देश भर में सुविधाजनक यात्रा प्रदान करने की दिशा में भारतीय रेल के निरंतर प्रयास को दर्शाते हैं।

माल ढुलाई में वृद्धि

भारतीय रेल ने जून 2026 में 142.21 मिलियन टन माल ढुलाई की, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह आंकड़ा 136.71 मिलियन टन था, जो 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। माल ढुलाई से लगभग 430 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ, जो जून 2025 की तुलना में 3 प्रतिशत अधिक है।

जून माह के दौरान कई प्रमुख वस्तुओं की ढुलाई में उत्साहजनक वृद्धि रही। उर्वरक की ढुलाई में 19.1 प्रतिशत, अन्य वस्तुओं में 17.3 प्रतिशत, लौह अयस्क में 9.4 प्रतिशत, घरेलू कोयले की ढुलाई में 4.9 प्रतिशत, कुल कोयले में 3.6 प्रतिशत और क्लिंकर (ठोस, गहरे भूरे या काले रंग का पदार्थ जो मुख्य रूप से सीमेंट बनाने के कारखानों में चूना पत्थर और मिट्टी को उच्च तापमान पर गर्म करने पर बनता है) में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों से निरंतर मांग को दर्शाती है।

जून 2026 में मजबूत प्रदर्शन वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में दर्ज निरंतर वृद्धि पर आधारित है। इस तिमाही में भारतीय रेल ने 419.08 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि में यह 413.05 मिलियन टन थी। इस तिमाही में कई प्रमुख कच्चे माल संवर्ग की ढुलाई में भी उत्साहजनक वृद्धि रही। इनमें लौह अयस्क में 7.44 प्रतिशत, क्लिंकर में 6.54 प्रतिशत और शेष एवं अन्य वस्तुओं की ढुलाई में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.16 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई।

ग्रीष्मकालीन मौसम में ताप विद्युत संयंत्रों की बढ़ी हुई आवश्यकता पूरी करने के लिए, भारतीय रेल ने घरेलू कोयला ढुलाई तेज की जिससे जून 2026 के दौरान पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बिजली संयंत्रों को 7 प्रतिशत अधिक कोयले की आपूर्ति हुई। इससे देश में निर्बाध बिजली उत्पादन को समर्थन मिला।

यात्री यातायात में लगातार वृद्धि

जून 2026 में यात्री आवागमन में भी स्थिर वृद्धि रही। भारतीय रेल ने 63.81 करोड़ यात्रियों को परिवहन सुविधा प्रदान की, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में यह संख्या 62.37 करोड़ थी।

उपनगरीय क्षेत्रों से इतर (अल्प और लंबी दूरी की यात्रा में) यात्रियों की संख्या में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि रही, जो 28.90 करोड़ से बढ़कर 30.04 करोड़ हो गई। उपनगरीय क्षेत्रों में भी 0.9 प्रतिशत की सकारात्मक बढोत्तरी दर्ज हुई, जहां यात्रियों की संख्या 33.46 करोड़ से बढ़कर 33.77 करोड़ हो गई।

आधुनिक यात्री सेवाओं में विस्तार

भारतीय रेल का प्रीमियम ट्रेन सेवाओं के विस्तार के साथ ही यात्री सेवाओं का आधुनिकीकरण जारी है। वंदे भारत सेवाओं की संख्या बढ़कर 164 हो गई है, जिसमें हाल ही में आरंभ की गई हावड़ा और कामाख्या के बीच चलाई गई वंदे भारत स्लीपर सेवा शामिल है। अमृत भारत ट्रेन सेवाओं की संख्या 72 तक पहुंच गई है, जिसमें जून 2026 में चार नई सेवाओं का उद्घाटन किया गया है। इससे देशभर में किफायती और आधुनिक लंबी दूरी के रेल संपर्क में मजबूती आई है।

माल ढुलाई और यात्री यातायात में निरंतर वृद्धि भारतीय रेल के कुशल प्रचालन तंत्र, विश्वसनीय यात्री सेवाओं और आधुनिक रेल अवसंरचना प्रदान करने की प्रतिबद्धता दर्शाती है। निरंतर क्षमता वर्धन, परिचालन दक्षता में सुधार और ग्राहक-केंद्रित पहल द्वारा भारतीय रेल देश में सुरक्षित, विश्वसनीय और यात्री-अनुकूल परिवहन सेवाएं प्रदान कर भारत के आर्थिक विकास में सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय रेलवे में साफ-सफाई पर कड़ा रुख: रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल मुख्यालयों से मांगा जवाब

सूत्र - रे.स.ब्यू - लंबी दूरी की ट्रेनों में गंदगी और खराब टॉयलेट्स की शिकायतों पर अब रेलवे बोर्ड बेहद सख्त नजर आ रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की एक हालिया रिपोर्ट में ट्रेनों की स्वच्छता को लेकर उठाए गए गंभीर सवालों के बाद, रेलवे बोर्ड ने देश के सभी जोनल रेलवे से इस पर विस्तृत और स्पष्ट जवाब तलब किया है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के महाप्रबंधकों (General Managers) को एक आधिकारिक पत्र भेजकर ऑडिट में सामने आई कमियों पर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

संसद में पिछले साल 20 अगस्त को ''भारतीय रेलवे में लंबी दूरी की ट्रेनों में स्वच्छता'' शीर्षक के साथ पेश की गई यह ऑडिट रिपोर्ट मुख्य रूप से साल 2018-19 से लेकर 2022-23 तक की अवधि के कामकाज पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर उजागर किया गया है कि लंबी दूरी के सफर में यात्रियों को मिलने वाली सफाई व्यवस्था उम्मीद के मुताबिक नहीं है। इसके साथ ही, यात्रियों से मिलने वाले फीडबैक और धरातल की असली हकीकत में काफी बड़ा अंतर देखने को मिला है। रिपोर्ट में स्वच्छता से जुड़े बजट और रेलवे के वित्तीय प्रबंधन में भी गंभीर कमियों की बात कही गई है।

कैग (CAG) ने इस मामले में रेलवे बोर्ड से केवल स्पष्टीकरण ही नहीं मांगा, बल्कि पुख्ता आंकड़ों की भी मांग की है। विभिन्न जोनल रेलवे द्वारा चलाए जा रहे 'क्लीन ट्रेन स्टेशन' (CTS) और 'ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस' (OBHS) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रभावी रूप से लागू होने के दावों को जांचने के लिए बोर्ड से ठोस प्रमाण पेश करने को कहा गया है। रेलवे बोर्ड ने अब साफ कर दिया है कि इस ऑडिट में सामने आई सभी आपत्तियों पर रेल मंत्रालय के ''कार्रवाई नोट'' के साथ जोनल रेलवे को जल्द से जल्द अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

सुरक्षा की ओर एक कदम, ट्रेन में यात्रा कर रही महिलाओं की हमसफर बन रही 'मेरी सहेली'

सूत्र - रे.स.ब्यू - मंडल रेल प्रबंधक आगरा श्री गगन गोयल के दिशा निर्देशन व वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री पी. राज मोहन के निर्देशन में आगरा मंडल में आरपीएफ ने अप्रैल से जून 2026 तक यात्रा के दौरान महिला यात्रियों की सहायता के लिए ऑपरेशन ''मेरी सहेली'' शुरू किया गया है, इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ की टीमो द्वारा कुल 64,800 महिला यात्रियों को सहायता प्रदान की गई है।

रेलवे प्रशासन इन दिनों ट्रेनों में अकेली यात्रा कर रही महिलाओं को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो और सुरक्षित उनको गंतव्य तक पहुंचने के लिए मेरी सहेली योजना चलाई जा रही है। यह योजना लंबी दूरी की ट्रेनों में लागू किया गया है। जनसम्पर्क अधिकारी श्री संजय कुमार गौतम ने बताया कि मेरी सहेली योजना के तहत अकेली महिला यात्रियों की यात्रा की पूरी जानकारी गाड़ी के प्रारंभ स्टेशन से ही अगले नामित स्टेशनों में रेलवे सुरक्षा बल की महिला बल को दी जाती है। जिससे स्टेशन में ट्रेन के आगमन होते ही मेरी सहेली की टीम ट्रेनों में जाकर महिला यात्रियों से संपर्क कर बात करती है, साथ ही उनको होने वाली परेशानियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में इन दिनों अकेली यात्रा कर रही महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। इसमें महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई है, जो आगरा मण्डल से गुजरने वाली सभी ट्रेनों की जांच कर महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान कर रही है।

संपादकीय

सफर आलीशान, सोच कंगाल: रेलवे की चादरों पर हाथ साफ करने वाला यह कैसा 'एलीट क्लास'?

वंदे भारत की रफ्तार और चमचमाते रेलवे स्टेशनों को देखकर लगता है कि हम एक आधुनिक राष्ट्र बन रहे हैं। लेकिन जैसे ही एसी कोच का सफर खत्म होता है और रेलवे का स्टाफ चादरें और तौलिये गिनना शुरू करता है, हमारी असलियत सामने आ जाती है। ट्रेनों से सरकारी तौलिये और चादरें गायब होने की बीमारी पुरानी है, पर शर्मनाक यह है कि इसे अंजाम कोई मजबूर व्यक्ति नहीं, बल्कि समाज का 'एलीट' और शिक्षित वर्ग दे रहा है।

हजारों रुपये का एसी टिकट लेकर चलने वाले इन तथाकथित वीआईपी यात्रियों का सिविक सेंस एक तौलिये के सामने दम तोड़ देता है। सफर खत्म होते ही चादर को चुपके से बैग में सरका लेना कौन सी अमीरी या समझदारी है? यह सीधे तौर पर एक मानसिक दिवालियापन है, जहाँ मुफ्त में सरकारी सामान पर हाथ साफ करने को लोग अपना अधिकार समझ लेते हैं।

विडंबना देखिए, यही लोग अगर ट्रेन पांच मिनट लेट हो जाए या प्लेटफॉर्म पर धूल दिख जाए, तो तुरंत सोशल मीडिया पर सरकार और प्रशासन को कोसने लगते हैं। उनके ट्वीट में देश को सुधारने की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। लेकिन क्या सरकार पर उंगली उठाने वाले इन जागरूक नागरिकों को बंद केबिन में अपनी इस हरकत पर शर्म नहीं आती? सरकारें ट्रेनें बदल सकती हैं, सीटें आरामदायक कर सकती हैं, लेकिन नागरिकों की नीयत को बदलने का कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता। जब तक हम सार्वजनिक संपत्ति को 'मुफ्त का माल' समझना बंद नहीं करेंगे, तब तक नई ट्रेनें भी हमारी पुरानी सोच को नहीं ढक पाएंगी।

हाईटेक होगा अहमदाबाद का रेलवे नेटवर्क: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने परखीं विकास योजनाएं, जल्द दिखेगा बड़ा बदलाव

सूत्र - रे.स.ब्यू - केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के अहमदाबाद आगमन पर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अहमदाबाद महानगर के जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर शहर एवं रेलवे अवसंरचना से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है तथा परियोजना का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2027 में सूरत बिलिमोरा खंड पर बुलेट ट्रेन सेवा का प्रथम चरण प्रारंभ किया जाएगा। इसके पश्चात क्रमिक रूप से वापी सूरत, अहमदाबाद तथा अंततः मुंबई तक परियोजना का विस्तार किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अहमदाबाद सहित पूरे गुजरात में विश्वस्तरीय रेलवे अवसंरचना, आधुनिक स्टेशन, बेहतर सड़क संपर्क तथा अत्याधुनिक परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी, शहरी यातायात सुगम होगा तथा क्षेत्र के समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। बैठक के उपरांत केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री द्वारा 28 फरवरी एवं 31 मार्च को साणंद में दो अन्य सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा चुका है।

बैठक के दौरान अहमदाबाद शहर एवं रेलवे से जुड़े निम्नलिखित पाँच प्रमुख विकास कार्यों पर निर्णय लिया गया।

ओमनगर अंडरपास (ROB) कार्य में तेजी

केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओमनगर अंडरपास का शेष कार्य आगामी नवरात्रि महोत्सव से पूर्व हर हाल में पूरा किया जाए, ताकि नागरिकों को शीघ्र यातायात सुविधा उपलब्ध हो सके।

असारवा स्टेशन एवं टर्मिनल का व्यापक पुनर्विकास

असारवा क्षेत्र के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए असारवा स्टेशन के लिए एक समग्र मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत नया स्टेशन भवन, आधुनिक यात्री सुविधाएँ तथा डीआरएम कार्यालय सहित आसपास के रेलवे क्षेत्र का समेकित विकास कर इसे एक आधुनिक एवं सुव्यवस्थित टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा।

अहमदाबाद स्टेशन पर सारंगपुर की ओर द्वितीय प्रवेश द्वार

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के अंतर्गत सारंगपुर दिशा से दूसरे प्रवेश द्वार एवं सड़क संपर्क के विकास पर भी सहमति बनी। इससे यात्रियों को स्टेशन तक बेहतर एवं सुगम पहुँच उपलब्ध होगी तथा आसपास के क्षेत्र का समुचित विकास संभव होगा।

शाहपुर-अहमदाबाद फ्लाईओवर परियोजना

शाहपुर अहमदाबाद फ्लाईओवर के निर्माण के संबंध में भारतीय पुरातत्व एवं राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण से जुड़े विषयों पर आवश्यक समन्वय स्थापित करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय संस्कृति मंत्री से चर्चा की गई है तथा सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त कर परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा।

साबरमती स्टेशन रोड विस्तार

साबरमती रेलवे स्टेशन तक बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्टेशन रोड के विस्तार एवं समग्र विकास के लिए संयुक्त कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति बनी। इससे यात्रियों एवं स्थानीय नागरिकों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध होगी। बैठक में अहमदाबाद महानगर भाजपा अध्यक्ष श्री प्रेरकभाई शाह, महामंत्री श्री दर्शक ठाकर, श्री गौतमभाई कथीरिया, श्री उमंगभाई नायक, अहमदाबाद महानगरपालिका के महापौर श्री हितेशभाई बारोट, उपमहापौर श्रीमती अंजूबेन शाह, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष श्री कमलेशभाई पटेल, नगर निगम में भाजपा नेता श्री जशुभाई ठाकोर, मुख्य सचेतक श्री अतुलभाई मिश्रा तथा पार्षद श्री सनी खांचंदानी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

दक्षिण कोरिया के मेसर्स ए.आर.ए. ब्रिज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री शियुंग पार्क ने किया बरेका का दौरा

सूत्र - रे.स.ब्यू - बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) में दिनांक 02 जुलाई 2026 को रिपब्लिक ऑफ कोरिया की प्रतिष्ठित कंपनी मेसर्स ए.आर.ए. ब्रिज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री शियुंग पार्क ने मेसर्स राइट्स लिमिटेड के अधिकारियों के साथ स्टैंडर्ड गेज लोकोमोटिव निर्माण क्षमता के आकलन हेतु बरेका का दौरा किया। उनके साथ मेसर्स जे. सी.एल. इन्फ्रा इंडिया के प्रबंध निदेशक श्री विश्व वासु गुप्ता भी उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (उत्पादन एवं विपणन) श्री राम जन्म चौबे ने किया। इस अवसर पर राइट्स के महाप्रबंधक श्री संजय कुमार एवं सहायक प्रबंधक श्री रोहित कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

दौरे की शुरुआत प्रशासन भवन स्थित कीर्ति कक्ष में आयोजित बैठक से हुई, जहाँ मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (उत्पादन एवं विपणन) श्री राम जन्म चौबे तथा मुख्य अभिकल्प इंजीनियर (डीजल) श्री प्रवीण कुमार ने पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बरेका की उपलब्धियों, तकनीकी प्रगति, लोकोमोटिव उत्पादन, वैश्विक निर्यात, आधुनिक विनिर्माण क्षमता तथा लोकोमोटिव निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न तकनीकी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में उप मुख्य विपणन प्रबंधक श्री अरविंद कुमार सहित बरेका के अनेक अधिकारी उपस्थित रहे।

इसके उपरांत प्रतिनिधिमंडल ने ट्रक मशीन शॉप, लोको फ्रेम शॉप, लोको असेंबली शॉप, लोको टेस्ट शॉप, लाइट मशीन शॉप, सब-असेंबली शॉप, इंजन इरेक्शन शॉप तथा इंजन टेस्ट शॉप सहित विभिन्न उत्पादन इकाइयों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्हें लोकोमोटिव निर्माण के विभिन्न चरणों, अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधाओं तथा बरेका की डिजाइन एवं उत्पादन क्षमताओं से अवगत कराया गया।

प्रतिनिधिमंडल ने बरेका की आधुनिक उत्पादन अवसंरचना, तकनीकी दक्षता तथा उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सुविधाओं की सराहना की। इस दौरे को भविष्य में संभावित औद्योगिक व्यावसायिक अवसरों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने बरेका के प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर श्री विवेक शील से शिष्टाचार भेंट भी की। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (उत्पादन एवं विपणन) श्री राम जन्म चौबे ने श्री शियुंग पार्क को स्मृति-चिह्न स्वरूप बरेका द्वारा निर्मित लोकोमोटिव मॉडल भेंट कर सम्मानित किया।

रेल की हर अपडेट अब आपके मोबाइल पर
बस स्कैन करें यह कोड

रेल समाचार ब्यूरो
की वेबसाइट पर खबरें पढ़ने के लिए अभी स्कैन करें

पाठकों से अनुरोध

विगत वर्षों की भाँति आगामी वर्ष के लिए अपनी रेल समाचार ब्यूरो पत्रिका को सुरक्षित करने के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क शीघ्र भेजने की कृपा करें, जिससे उक्त पत्रिका आपको नियमित भेजी जा सके।

सहयोग राशि:

१. उच्चतम अधिकारी-5000 रु. मात्र
२. उच्च अधिकारी- 3500 रु. मात्र
३. अधीनस्थ अधिकारी-2500 रु. मात्र
४. रेलकर्मी/अन्य सदस्य-1000 रु. मात्र

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
पंजीकृत कार्यालय
502 पंचशीला भवन त्रिवेणी रोड, नेतानगर, कीडगंज प्रयागराज-211003 से प्रकाशित।
कैंप कार्यालय- अनिल जैन (रिपोर्टर) कार्यालय 8439 आर्य नगर पहाड़गंज दिल्ली-55

समस्त प्रकार के कानूनी मामलों का न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
दि. इलाहाबाद ब्लॉक वर्क्स प्रा. लि.
329/255 चक, जीरो रोड इलाहाबाद से मुद्रित एवं 502 पंचशीला भवन त्रिवेणी रोड, नेतानगर, कीडगंज प्रयागराज-211003 से प्रकाशित।
आर.एन. आई नं. 51097-90 पोस्ट ए.डी.-8
मो. 9773946044 / 9793956044
फोन नं. 0532-2418040

Scanned with OKEN Scanner

टनकपुर-नांदेड़ और नांदेड़-मुंबई समेत शुरू हुई नई रेल सेवाएं

सूत्र - रे.स.ब्यू - केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा ने 06 जुलाई, 2026 को टनकपुर, नांदेड एवं पीलीभीत स्टेशन से टनकपुर-नांदेड एक्सप्रेस, नांदेड-मुंबई एक्सप्रेस तथा टनकपुर-पीलीभीत ट्रेन सेवा का शाहजहाँपुर तक विस्तार का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया।

समारोह को सम्बोधित करते हुये केन्द्रीय रेलमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नांदेड के धार्मिक महत्व एवं जन भावनाओं को देखते हुए टनकपुर-नांदेड एक्सप्रेस एवं नांदेड-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेनों के संचलन को स्वीकृति प्रदान की गयी और इन गाड़ियों का संचलन प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त टनकपुर-पीलीभीत ट्रेन सेवा का शाहजहाँपुर तक विस्तार का शुभारंभ किया जा रहा है। भारतीय रेल में ट्रांसमेशन का कार्य तेजी से चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने रेलवे पर विशेष ध्यान दिया है तथा प्रत्येक राज्य को पहले से कई गुना बजट आवंटित किया जा रहा है। पिछले 12 वर्षों में 37000 किमी. नये टैक बनाये गये तथा 99.6 प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है, शेष शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा। बुलेट ट्रेन परियोजना पर कार्य तेजी से चल रहा है। अगले वर्ष बुलेट ट्रेन चालू हो जायेगी । पूर्वी एवं पश्चिमी कॉरिडोर का कार्य पूर्ण हो चुका है। पूर्वी एवं पश्चिमी कॉरिडोर को जोड़ने के लिये कार्य किया जायेगा।

माननीय रेल मंत्री श्री वैष्णव ने कहा कि काफी नई ट्रेनें चलाई गई हैं। भारतीय रेल गरीबों एवं मध्यम वर्ग की सवारी हैं इसलिये अफोंडेबल सेवा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सामान्य द्वितीय श्रेणी के 12000 नये कोचों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 4000 कोच बनकर गाड़ियों में लगाये गये हैं जिसका अच्छा लाभ मिला है। इस समर सीजन में रिकार्ड संख्या में ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियाँ चलाई गई। पिछले दीपावली एवं छठ पर्वों पर 12000 विशेष ट्रेनें चलाई गईं। उन्होंने कहा कि आगामी रथ यात्रा के पावन पर्व पर 300 तथा ओणम पर्व में 100 विशेष ट्रेनें चलाई जायेंगी। रेल मंत्री ने सम्मानित जनप्रतिनिधियों की रेल सम्बन्धी मांगों पर विचार का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री, उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर-नांदेड एक्सप्रेस तथा टनकपुर-पीलीभीत ट्रेन सेवा का शाहजहाँपुर तक विस्तार के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा की उत्तराखंड, विशेष रूप से कुमायूं क्षेत्र के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। टनकपुर-नांदेड एक्सप्रेस का शुभारम्भ ही नही वरन् उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच आस्था, विकास, पर्यटन एवं सांस्कृतिक एकता का एक सशक्त सेतु है। टनकपुर कुमायूं क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। यहीं से मार्ग पूर्णागिरि मंदिर, आदिकैलाश जाता है। यहाँ की जनता की काफी दिनों से मांग थी कि मध्य एवं दक्षिण भारत के लिये ट्रेन चलाई जाय, जिससे महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ते हुये उत्तराखण्ड पहुंचा जा सके। इस ट्रेन के संचलन से महाराष्ट्र से उत्तराखण्ड आने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को नया बाजार मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई रेल लाइन परियोजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को लक्ष्य कर उत्तराखण्ड मे अमृत भारत स्टेशनों का पुनर्विकास कर उन्नत यात्री सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

ऐतिहासिक उपलब्धि: उत्तर रेलवे केंद्रीय अस्पताल (NRCH) ने किया नेशनल सर्जिकल स्किल कोर्स का सफल आयोजन

पहली बार, राष्ट्रीय स्तर के FMAS AMASI प्रशिक्षण कार्यक्रम में 277 प्रतिनिधियों और 80 शीर्ष संकाय सदस्यों (फैकल्टी) ने नई दिल्ली में लिया हिस्सा

सूत्र - रे.स.ब्यू - उत्तर रेलवे केंद्रीय अस्पताल (NRCH), नई दिल्ली से संबद्ध इंडियन रेलवे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट अ फ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (IRPGIMSR) के सर्जरी विभाग ने हाल ही में ''126वें FMAS AMASI स्किल कोर्स'' की सफल मेजबानी करके इतिहास रच दिया है। यह ऐतिहासिक आयोजन रेलवे चिकित्सा सेवाओं के इतिहास में पहली बार है, जब इस संस्थान द्वारा 'मिनिमल एक्सेस सर्जरी' (दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी) में इस प्रमुख, राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस प्रतिष्ठित शैक्षणिक आयोजन ने उन्नत सर्जिकल कौशल विकास के लिए एक असाधारण मंच प्रदान किया, जिसमें पूरे भारत से 277 प्रतिनिधियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान, देश के कुछ सबसे अनुभवी और प्रसिद्ध लेप्रोस्कोपिक सर्जनों और स्त्री रोग विशेषज्ञों सहित 80 प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

उद्घाटन समारोह में डॉ. प्रो. रुशमा टंडन (निदेशक और पीसीएमडी, IRPGIMSR और NRCH, नई दिल्ली) ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सम्मेलन की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जो आधुनिक सर्जिकल शिक्षा में ज्ञान, नवाचार और उत्कृष्टता के प्रयास का प्रतीक है।

प्रतिनिधियों और संकाय दोनों की ओर से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया ने 126वें FMAS AMASI स्किल कोर्स को एक बड़ी सफलता के रूप में स्थापित कर दिया है। अनुभवी दिग्गजों और उभरते सर्जनों के बीच की दूरी को पाटकर, इस आयोजन ने IRPGIMSR और NRCH, नई दिल्ली को भारत में चिकित्सा नवाचार, सर्जिकल शिक्षा और व्यावसायिक कौशल वृद्धि के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में और अधिक मजबूती से स्थापित किया है।

इस गहन पाठ्यक्रम के दौरान, प्रतिनिधियों को एक व्यापक पाठ्यक्रम का लाभ मिला, जिसमें शामिल थेः

- लाइव सर्जिकल प्रदर्शनः उन्नत लेप्रोस्कोपिक तकनीकों का प्रदर्शन करने वाले रीयल-टाइम प्रसारण।
- व्यावहारिक (हैंड्स-ऑन) कौशल प्रशिक्षणः सर्जिकल सटीकता को और बेहतर बनाने के लिए तैयार किए गए व्यावहारिक सत्र।
- इंटरएक्टिव अकादमिक मंचः 'मिनिमल एक्सेस सर्जरी' में नवीनतम प्रगति पर प्रख्यात राष्ट्रीय संकाय के नेतृत्व में गहन चर्चा।

प्रयागराज मंडल परिक्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक आयोजित

बैठक में जन सरोकारों और रेलवे के विकास कार्यों पर हुई चर्चा

सूत्र - रे.स.ब्यू - उत्तर मध्य रेलवे में दिनांक 10 जुलाई 2026 को प्रयागराज के प्रतिष्ठित होटल कान्हा श्याम के सभागार में उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मण्डल के माननीय सांसदों एवं उनके सम्मानित प्रतिनिधियों के साथ महाप्रबंधक की एक उच्च स्तरीय एवं महत्वपूर्ण बैठक का माननीय सांसद-अलीगढ़ श्री सतीश कुमार गौतम की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य मण्डल की हालिया उपलब्धियों को साझा करना, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की समीक्षा करना तथा माननीय जनप्रतिनिधियों से बहुमूल्य सुझाव प्राप्त कर रेल विकास योजनाओं को नई दिशा देना रहा।

इस अवसर पर अपने उदबोधन में महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे श्री नरेश पाल सिंह ने कहा कि, हमने अपनी रेलवे की कार्यप्रणाली में लाइन क्षमता की वृद्धि, यात्री सुविधाओं में सुधार एवं उन्नयन, गाड़ियों का संरक्षित संचालन, कर्मचारी कल्याण, पर्यावरण की संरक्षण के लिए हरित पहल की दिशा में विशेष कदम उठाए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और इसे मजबूत बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों से एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आया है, रेल की विभिन्न परियोजनाएं जो वर्षों तक पर्याप्त फंड की अनुपलब्धता के कारण रुक जाते थे, उन कार्यों को करने हेतु सरकार द्वारा अब पर्याप्त फंड भी उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही उच्चतम स्तर से प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग होने से प्रोजेक्ट पूर्ण होने में तेजी आई है। साथ ही भारतीय रेल अपनी कार्यप्रणाली में इनोवेशन और आधुनिक तकनीक का कारगर प्रयोग कर रहे हैं। हम अपने सम्मानित यात्रियों, रेल उपयोगकर्ताओं और आमजन की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें, इस हेतु एआई आधारित रेल मदद पोर्टल (139) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि , प्रयागराज मण्डल, भारतीय रेल के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में रेल की सेवा में निरन्तर तत्पर है। हमारा यह मंडल उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण हिस्सों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने का कार्य कर रहा है। मंडल की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए श्री सिंह ने बताया कि, वित्त वर्ष 2025-26 में कुल आरंभिक यात्री संख्या लगभग 7.40 करोड़ रही एवं यात्री आय के रूप में 1699 करोड़ रुपये और माल लदान से लगभग 893 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई।

उन्होंने बताया कि जनमानस की मांग को ध्यान में रखते हुए हाल ही में प्रयागराज दादरी स्पेशल ट्रेन (02417/18) का संचालन प्रारम्भ किया गया, जिससे नोएडा एनसीआर एवं जेवर एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को विशेष सुविधा प्राप्त हुई । इसके अतिरिक्त मेला, समर, त्योहार एवं परीक्षा विशेष सहित कुल 14,127 विशेष ट्रिप संचालित किए गए तथा 24 जोड़ी

विशेष गाड़ियों का संचालन किया गया। अमृत भारत, वंदे भारत एवं राजधानी सहित 18 जोड़ी नई गाड़ियों का संचालन प्रारम्भ किया गया। वहीं 04 जोड़ी MEMU ट्रेनों को 8-कार से बढ़ाकर 12-कार किया गया।

स्टेशन री-डेव्लपमेंट एवं अमृत स्टेशन के विषय में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रयागराज मण्डल में कुल 02 प्रमुख रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन एवं कानपुर सेंट्रल को स्टेशन रीडेवलेपमेंट प्लान के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है।इसके अतिरिक्त प्रयागराज मण्डल में अमृत भारत योजना के अंतर्गत शामिल 15 स्टेशनों में से 5 स्टेशनों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष का कार्य प्रगति पर है, जिसे इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर की चर्चा करते हुए सूचित किया कि, इसकी वृद्धि के तहत प्रयागराज मण्डल द्वारा 28 किमी. की रेलवे लाईन बिछाई गयी और 03 ब्लॉक सेक्शनों के तृतीय लाइन में 25.18 KM इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आधारित ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली सफलतापूर्वक चालू की गई। कुल 400 KM में कवच प्रणाली का सफल कमीशनिंग किया गया, जिससे ट्रेन संचालन की सुरक्षा एवं विश्वसनीयता में वृद्धि हुई।

इसी क्रम में उन्होंने सभी माननीय सांसदगणों को आश्वस्त किया कि आपसे प्राप्त बहुमूल्य सुझावों पर गंभीरता से अध्ययन किया जायेगा तथा प्रयागराज मण्डल के स्तर पर इन सुझावों को रेल विकास योजनाओं एवं यात्री सुविधाओं में शामिल किया जायेगा। यदि कोई सुझाव क्षेत्रीय रेलवे के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है,तो प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड एवं अन्य जोनों में भेजा जाएगा।

महाप्रबंध महोदय के संबोधन उपरांत वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक द्वारा प्रयागराज मंडल में किए जा रहे विकास कार्यों पर एक पावरप्वाइंट प्रस्तुतिकरण किया। इसके बाद माननीय सांसद महोदयों एवं शेष माननीय सांसद महोदयों के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव एवं मांगें रखी गई। इनमें मुख्यतः आम जनता के सरोकारों के विषय थे जिनमें नई ट्रेन सेवाएं, ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी एवं ठहराव, प्रमुख स्टेशनों का पुनर्विकास एवं यात्री सुविधाओं का विस्तार, रेल अवसंरचना एवं नेटवर्क क्षमता में वृद्धि, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन एवं स्टेशन परिसर व्यवस्था, बुनियादी यात्री सुविधाओं की गुणवत्ता एवं रखरखाव आदि प्रमुख रहे।

Scanned with OKEN Scanner

President of India Smt. Droupadi Murmu inaugurates 'Saushrutam 2026' calls for integration of traditional wisdom with modern science to strengthen evidence-based Ayurveda

Global experts from nine countries converge at AIIA to advance evidence-based Ayurvedic surgical sciences

Source/RSB- The President of India, Smt. Droupadi Murmu, inaugurated Saushrutam 2026, a three-day international seminar on Ayurvedic surgery, at the All India Institute of Ayurveda (AIIA), New Delhi. The seminar is being organised by AIIA under the Ministry of Ayush on the occasion of Sushruta Jayanti and has brought together eminent surgeons, researchers, academicians and policymakers from India and abroad.

On the occasion, the President inaugurated a state-of-the-art AI-enabled 3 Tesla High-Field MRI facility at AIIA and witnessed the release of the National Commission for Indian System of Medicine (NCISM) study titled Evaluation of Professional Career of Ayurveda Female Graduates – An Observational Exploratory Study. The President said Acharya Sushruta's pioneering contributions laid the foundation of scientific and systematic surgical practices in the world and that Ayurveda's holistic approach to health continues to hold relevance in modern healthcare. She said preserving biodiversity is essential for the sustainable growth of Ayurveda and stressed the need to ensure the availability of medicinal plants while strengthening traditional knowledge through scientific validation.

The President called for greater participation of women in the Ayurveda workforce and urged collective efforts to address the challenges women professionals face in building long-term careers. Commending the Ministry of Ayush for promoting Ayurveda globally, she said the integration of traditional knowledge with advanced technologies, modern diagnostics and scientific research

is expanding the scope and credibility of the system. She expressed confidence that initiatives such as Saushrutam 2026 would further strengthen evidence-based practice and enhance the global acceptance of Ayurveda.

Union Minister of State (Independent Charge) for Ayush and Minister of State for Health & Family Welfare, Shri Prataprao Jadhav, said that under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, Ayurveda has gained unprecedented global recognition and renewed momentum, with Saushrutam 2026 providing an important platform for advancing excellence in Ayurvedic surgery while fostering international cooperation. Referring to the NCISM study, he highlighted the challenges faced by women Ayurveda graduates in career progression and emphasised the need for policy interventions and institutional support to increase their participation in leadership, research and clinical practice. He also underlined the importance of empowering young Ayurveda professionals to contribute to nation-building and global healthcare.

Welcoming the dignitaries, Prof. (Vd.) P. K. Prajapati, Director, AIIA, said Saushrutam 2026 marks a significant milestone in integrating classical Ayurvedic surgical knowledge with contemporary scientific advancements. He said the seminar would strengthen academic collaboration, promote high-quality research and enhance clinical excellence in Ayurvedic surgery at both the national and international levels. The newly inaugurated AI-enabled 3 Tesla High-Field MRI facility will significantly strengthen diagnostic services at AIIA, facilitate integrative research between Ayurveda and modern medicine, and provide affordable, high-quality imaging services to patients.

विशेष रेलगाड़ियों के अतिरिक्त फेरों का संचालन

भारतीय रेल द्वारा अपने सम्मानित रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष रेलगाड़ियों के संचालन अवधि में विस्तार का निर्णय लिया गया है। यह रेलगाड़ियाँ अपने पूर्व निर्धारित समय, ठहराव, संरचना एवं मार्ग पर चलेंगी, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

गाड़ी सं.	स्टेशन से - स्टेशन तक	विस्तारित अवधि की तिथि	
		से	तक
01907	आगरा कैंट-उधना	21.07.2026	25.08.2026
01908	उधना-आगरा कैंट	22.07.2026	26.08.2026
04139	प्रयागराज-दादर	17.07.2026	28.08.2026
04140	दादर-प्रयागराज	19.07.2026	30.08.2026
04125	सूबेदारगंज-बान्द्रा (ट.)	20.07.2026	31.08.2026
04126	बान्द्रा (ट.)-सूबेदारगंज	21.07.2026	01.09.2026
02199	वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी-बान्द्रा (ट.)	16.07.2026	27.08.2026
02200	बान्द्रा (ट.)-वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	18.07.2026	29.08.2026
01905	कानपुर सेंट्रल-असारवा	20.07.2026	31.08.2026
01906	असारवा-कानपुर सेंट्रल	21.07.2026	01.09.2026
04155	सूबेदारगंज-उधना	16.07.2026	31.08.2026
04156	उधना-सूबेदारगंज	17.07.2026	01.09.2026
04111	प्रयागराज-गांधीग्राम	18.07.2026	29.08.2026
04112	गांधीग्राम-प्रयागराज	19.07.2026	30.08.2026
04119	सूबेदारगंज-वलसाड	18.07.2026	29.08.2026
04120	वलसाड-सूबेदारगंज	19.07.2026	30.08.2026
04177	सूबेदारगंज-वलसाड	21.07.2026	25.08.2026
04178	वलसाड-सूबेदारगंज	22.07.2026	26.08.2026
01910	आगरा कैंट-असारवा	03.08.2026	31.08.2026
01909	असारवा-आगरा कैंट	04.08.2026	01.09.2026
04105	प्रयागराज-उधना	02.08.2026	30.08.2026
04106	उधना-प्रयागराज	03.08.2026	31.08.2026
04175	सूबेदारगंज-दादर	19.07.2026	30.08.2026
04176	दादर-सूबेदारगंज	21.07.2026	01.09.2026

नोटः- ट्रेनों से सम्बंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन 139 या Rail Madad Mobile App या वेबसाइट railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें।

उत्तर मध्य रेलवे

@CPRONCR North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in 1614/26(A)

Ministry of Ayush signs MoU with University of Delhi to advance research, innovation and sustainable utilisation of medicinal plants

Source/RSB- In a significant step towards strengthening research and innovation in the medicinal plants sector, the National Medicinal Plants Board (NMPB), Ministry of Ayush, and the University of Delhi, through Bhaskaracharya College of Applied Sciences (BCAS), signed a Memorandum of Understanding (MoU) at Kartavya Bhawan, New Delhi. The MoU was signed in the presence of Shri Prataprao Jadhav, Union Minister of State (Independent Charge), Ministry of Ayush, and Minister of State for Health and Family Welfare.

The collaboration aims to establish a long-term partnership for scientific research, product development, innovation, value addition, post-harvest technologies, sustainable packaging, technology transfer and capacity building, while promoting the sustainable utilization and conservation of India's rich medicinal plant resources.

Addressing the gathering, Shri Prataprao Jadhav said the initiative is in line with the vision of Prime Minister Shri Narendra Modi of building a healthier, self-reliant and developed India by 2047. Describing the MoU as a landmark step, he said it would strengthen scientific research, promote innovation and unlock the vast potential of India's medicinal plant wealth through the integration of traditional knowledge with modern science.

The Minister observed that India possesses one of the world's richest repositories of medicinal plants and a centuries-old tradition of herbal healthcare. He emphasized that evidence-based research, innovation and value addition are essential to enhance the global credibility, competitiveness and market potential of India's medicinal plants sector.

Highlighting the broader impact of the partnership, Shri Jadhav said it would create new opportunities for young researchers, scientists and entrepreneurs, encourage innovation-led enterprises, generate livelihoods and contribute to the growth of India's bioeconomy. He expressed confidence that the collaboration would lead to the development of value-added products, sustainable technologies and farmer-centric solutions benefiting both industry and farming communities.

Speaking on the occasion, Shri Mahesh Dadhich, Chief Executive Officer, National Medicinal Plants Board (NMPB), emphasized the importance of research-driven innovation in enhancing farmers' income through medicinal plant cultivation. He highlighted the potential of developing eco-friendly and health-safe packaging materials derived from medicinal plant resources as sustainable alternatives to conventional aluminium-based packaging and other environmentally harmful materials.

He further noted that cultivating medicinal plants in suitable ecological zones, including riverine areas, can simultaneously promote biodiversity conservation, ecological restoration and sustainable livelihood generation for farming communities.

The collaboration will leverage BCAS's expertise in food technology, nutraceuticals, post-harvest processing and sustainable packaging. The institution's recent innovations, including patented technologies for value addition of biological resources, are expected to provide further impetus to translational research, technology commercialization and entrepreneurship in the medicinal plants sector. The MoU is expected to strengthen industry academia collaboration, accelerate technology transfer and enhance public awareness regarding the health, economic and environmental significance of medicinal plants.

The event was attended by Prof. Balaram Pani, Dean of Colleges, University of Delhi; Dr Abdul Qayum Director (Tech), senior officials of the Ministry of Ayush and NMPB; BCAS faculty members, researchers, and media representatives.

Scanned with OKEN Scanner

रेलवे माल ढुलाई में बड़ा बदलाव

अब विशेष कंटेनरों से होगा उर्वरकों का परिवहन,

'रिफॉर्म एक्सप्रेस' के तहत 8 बड़े सुधारों का ऐलान

भारतीय रेलवे में सुधारों का नया चरण, 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' के तहत अब तक 17 बड़े बदलाव

सूत्र - रे.स.ब्यू - रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे में माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक आधुनिक, दक्ष और पर्यावरण-अनुकूल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब उर्वरकों का परिवहन पारंपरिक बंद मालगाड़ियों के बजाय विशेष रूप से तैयार कंटेनरों के माध्यम से किया जा सकेगा।

रेल मंत्री ने बताया कि देश में उर्वरकों के परिवहन का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा रेलवे के माध्यम से होता है। ऐसे में कंटेनर आधारित व्यवस्था से उर्वरकों की ढुलाई, भंडारण और हैंडलिंग अधिक सुगम होगी। इस व्यवस्था का एक बड़ा लाभ यह होगा कि पूरी रेक को रोके बिना अलग-अलग कंटेनरों को आवश्यकतानुसार रखा और आगे भेजा जा सकेगा।

'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पहल को आगे बढ़ाते हुए रेल मंत्री ने भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए आठ और संरचनात्मक सुधारों की घोषणा की। इसके साथ ही इस पहल के तहत लागू सुधारों की कुल संख्या 17 हो गई है। ये सुधार माल ढुलाई, लॉजिस्टिक्स, निर्माण पद्धतियों, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, वैगन डिजाइन, कौशल विकास और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएंगे।

अश्विनी वैष्णव ने फ्लाई ऐश परिवहन में भी बड़े बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब फ्लाई ऐश का परिवहन खुले वैगनों के स्थान पर विशेष कंटेनरों में किया जाएगा। देश में हर साल लगभग 34 करोड़ टन फ्लाई ऐश का उत्पादन होता है, जिसका उपयोग सीमेंट और सड़क निर्माण जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। नई व्यवस्था से लोडिंग, परिवहन और भंडारण के दौरान धूल प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।

रेल मंत्री ने कंटेनर नीति के तहत एकीकृत लाइसेंस प्रणाली की भी घोषणा की। इससे रेलवे माल ढुलाई क्षेत्र में निजी निवेश, संचालन दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य इन सुधारों के माध्यम से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाना और भारतीय रेलवे को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है।

फ्लाई ऐश का परिवहन

भारत में हर साल लगभग 340 मिलियन टन फ्लाई ऐश पैदा होती है, जिसमें से लगभग 96 मिलियन टन का इस्तेमाल सीमेंट उद्योग द्वारा किया जाता है। भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 13 मिलियन टन फ्लाई ऐश का परिवहन किया, जो देश में कुल फ्लाई ऐश उत्पादन का लगभग चार प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक रूप से फ्लाई ऐश को खुले वैगनों में ढोया जाता रहा है, जिससे लोडिंग, परिवहन और अनलोडिंग के दौरान धूल से प्रदूषण होता है। थर्मल पावर प्लांट में बड़े ऐश पॉन्ड में जमा करने पर भी फ्लाई ऐश पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है।

इन समस्याओं को दूर करने के लिए, भारतीय रेलवे ने फ्लाई ऐश के परिवहन के लिए एक नई कंटेनर-आधारित व्यवस्था शुरू की है। नई नीति के तहत, परिवहन के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए आईएसओ-मानक कंटेनरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन कंटेनरों को पावर प्लांट से सीधे टॉप-लोडिंग सिस्टम के जरिए भरा जा सकता है और साइड-डिस्चार्ज या न्यूमैटिक सिस्टम का इस्तेमाल करके बिना धूल प्रदूषण फैलाए खाली किया जा सकता है।

श्री वैष्णव ने कहा कि बंद-कंटेनर व्यवस्था से प्रदूषण-मुक्त परिवहन मुमकिन होगा, सीमेंट प्लांट में जरूरत पड़ने तक सुरक्षित स्टोरेज आसान होगा और लॉजिस्टिक्स की क्षमता में भी काफी सुधार होगा। इन कंटेनरों को रीच स्टैकर्स के जरिए ले जाया जा सकता है, जिससे पावर प्लांट से सीमेंट प्लांट तक बिना किसी रुकावट के सामान की आवाजाही हो सकेगी। इस सुधार से फ्लाई ऐश की रेल से ढुलाई बढ़ने, सड़क परिवहन पर निर्भरता कम होने और पर्यावरण की चुनौती को आर्थिक रूप से फायदेमंद संसाधन में बदलने की उम्मीद है।

कंटेनर क्षेत्र में सुधार

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि थोक सामान के अलावा रेल माल ढुलाई में विविधता लाने के लिए ज़्यादा कंटेनराइजेशन की जरूरत है। कंटेनर ट्रैफिक को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रेलवे ने कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर लाइसेंसिंग व्यवस्था में एक बड़ा ढांचागत सुधार किया है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के तहत, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर (सीटीओ) लाइसेंस चार श्रेणियों (श्रेणी I-IV) में जारी किए जाते थे, जिसमें श्रेणी-I के लिए 50 करोड़ और बाकी कैटेगरी के लिए 10 करोड़ की पंजीकरण फीस लगती थी, साथ ही मार्ग से जुड़ी पाबंदियां और पंजीकरण से जुड़ी अलग-अलग जरूरतें भी थीं। अब इसकी जगह एक ही पैन-इंडिया कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर लाइसेंस लागू कर दिया गया है।

नई व्यवस्था के तहत, ऑपरेटर्स बिना किसी श्रेणी आधारित पाबंदी के पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क पर कंटेनर ट्रेनें चला सकेंगे। सभी मार्गों पर लागू 25 करोड़ की एक जैसी नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस के जरिए रजिस्ट्रेशन प्रणाली को भी आसान बना दिया गया है।

श्री वैष्णव ने आगे कहा कि ये अनुमति बीस साल तक मान्य रहेगी और सफल ऑपरेशन के आधार पर, बिना किसी रिन्यूअल या एक्सटेंशन फीस के इन्हें आगे बढ़ाया जा सकेगा। आसान लाइसेंसिंग व्यवस्था से कारोबार में आसानी होने, निजी भागीदारी बढ़ने, कंटेनराइजेशन के बढ़ने, रेलवे की ओर ज़्यादा नॉन-बल्क कार्गो आकर्षित होने, रसद लागत कम होने और देश की माल ढुलाई व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

खाद का परिवहन

कृषि क्षेत्र के लिए खाद की ढुलाई के महत्व पर जोर देते हुए, श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे अभी देश में खाद की लगभग 85 प्रतिशत ढुलाई का काम संभालता है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा माल ढुलाई व्यवस्था में करीब पचास अलग-अलग स्लैब थे, जिससे संचालन मुश्किल हो जाता था। नए सुधारों के तहत, माल ढुलाई के शुल्क को आसान बनाकर प्रति टन प्रति किलोमीटर के आधार पर कर दिया गया है, जिसमें तीन तरह की शुल्क संरचना शामिल हैं।

इन सुधारों के तहत कंटेनरों के जरिए भी खाद की ढुलाई की जा सकती है। पहले की व्यवस्था में पूरी रेक को एक ही जगह पर पूरा सामान उतारने तक रोकना पड़ता था, लेकिन अब अलग-अलग कंटेनरों को जरूरत के हिसाब से रेक पॉइंट पर उतारा और उन्हें संग्रहित किया जा सकता है। इससे वितरकों की जरूरतों और सामान उठाने की क्षमता के आधार पर विभिन्न चरणों में वितरण करना आसान हो जाएगा।

"इन सुधारों से परियोजनाएं तेजी से पूरी हो सकेंगी और रेलवे व्यवस्था में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा: अश्विनी वैष्णव"

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कंटेनर से ढुलाई करने पर वैगन के टर्नअराउंड में सुधार होगा, रेक के रुके रहने का समय कम होगा, वितरण में सुधरा होगा, खाद को बारिश और मौसम से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा और कुल मिलाकर लॉजिस्टिक्स की कार्यक्षमता बेहतर होगी।

रेलवे परियोजनाओं और कार्यों में कारीगरों को कौशल सिखाने की नीति

रेलवे की ढांचागत परियोजनाओं में सुरक्षा से जुड़े काम होते हैं, जिनके लिए खास कौशल, सटीक इंजीनियरिंग और कड़े गुणवत्तापूर्ण मानकों का पालन जरूरी होता है।

योग्य कार्यबल की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेलवे ने रेलवे परियोजनाओं और अन्य कार्यों में लगे कारीगरों को कौशल सिखाने के लिए एक व्यापक नीति शुरू की है। यह नीति वेल्डिंग, फिटिंग, चिनाई और निर्माण से जुड़े अन्य खास कार्यों में लगे कामगारों की पहचान, मूल्यांकन और प्रमाणीकरण के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करती है।

नए फ्रेमवर्क के तहत, परियोजना के हिसाब से जरूरी कौशल तय किए जाएंगे और कामगारों का प्रैक्टिकल और मौखिक मूल्यांकन तय परीक्षण अधिकारियों के जरिए किया जाएगा। सफल उम्मीदवारों को क्यूआर कोड वाले कौशल प्रमाणपत्र मिलेंगे, जो एक लाइव सत्यापन डेटाबेस से जुड़े होंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस नीति को लागू करने की शुरुआत बड़े और कठिन रेलवे परियोजनाओं जैसे पुल और सुरंगों से होगी और अगले 24 महीनों में इसे सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाईयों तक बढ़ाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस पहल से यह सुनिश्चित होगा कि खास रेलवे कार्यों में सिर्फ प्रमाणीकृत कारीगर और सुपरवाइजर ही लगाए जाएं, भारतीय रेलवे में कौशल का आकलन का एक मानक तरीका बने, जानकारियों का वास्तविक समय में सत्यापन आसान ढंग से हो, काम की गुणवत्ता बेहतर हो, गुणवत्ता आश्वासन मजबूत हो और देश के ढांचागत क्षेत्र में कौशल उन्नयन को बढ़ावा मिले।

निर्माण से संबंधित सुधार

इस साल की शुरुआत में शुरू किए गए ठेकेदार की योग्यता से जुड़े सुधारों की सफलता के बाद, भारतीय रेलवे ने अब निर्माण व्यवस्था को मजबूत करने और परियोजनाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए सुधारों का एक और बड़ा कदम उठाया है।

उन्होंने कहा कि इन सुधारों का मकसद कार्य के प्रति गंभीर और काबिल ठेकेदारों को बढ़ावा देना, निर्माण की गुणवत्ता बेहतर करना, विवाद कम करना और रेलवे की ढांचागत परियोजनाओं को समय पर पूरा करना है।

सुधारों के तहत, अब अनुबंध शुरू होने पर ही 10 प्रतिशत परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाएगी, न कि रनिंग बिल से कटौती करके इसे वसूला जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि रेलवे परियोजनाओं में सिर्फ गंभीर ठेकेदार ही हिस्सा लें और काम पूरा होने के दौरान उनकी जवाबदेही मजबूत हो।

कानूनी विवादों को बढ़ावा देने वाले अनुबंधों के तरीकों को रोकने के लिए, योग्यता के कड़े नियम भी लागू किए गए हैं। जिन ठेकेदारों का लंबित कानूनी मामला उनकी नेट वर्थ के 50 प्रतिशत से ज़्यादा है, वे रेलवे टेंडर में हिस्सा लेने के लिए योग्य नहीं होंगे।

इन सुधारों में कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क इंश्योरेंस और प्रोफेशनल इंडेम्निटी इंश्योरेंस भी शामिल किए गए हैं, ताकि प्रोजेक्ट पूरा होने के दौरान जोखिम प्रबंधन को मजबूत किया जा सके और निर्माण से जुड़े जोखिमों से सुरक्षा मिल सके।

श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे ने विवादों को कम करने और परियोजनाओं को समय पर शुरू करने में मदद के लिए जमीन सौंपने की एक साफ और क्रमवार प्रक्रिया भी बनाई है।

केंद्रीय मंत्री ने रेल भूमि का भी जिक्र किया, जो जमीन अधिग्रहण के पूरे प्रबंधन के लिए सीआरआईएस द्वारा बनाया गया एक वेब-बेस्ड प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म IRPSM, IPAS और HRMS जैसे रेलवे के कई एप्लिकेशन्स को एक साथ जोड़ता है, जिससे जानकारी का आसानी से आदान-प्रदान, जमीन अधिग्रहण के मुख्य चरणों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग, बेहतर कार्य प्रबंधन और डैशबोर्ड तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली के जरिए वास्तविक समय में निगरानी मुमकिन हो पाती है। उम्मीद है कि यह पोर्टल जमीन अधिग्रहण की रफ्तार बढ़ाएगा, परियोजनाओं की योजनाओं को बेहतर बनाएगा और रेलवे के ढांचागत कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करेगा।

वैगन डिजाइन मंजूरी के लिए पॉलिसी

एक और बड़े संरचनात्मक सुधार के बारे में बताते हुए, श्री वैष्णव ने वैगन डिजाइन मंजूरी के लिए एक नई नीति की घोषणा की। इसका मकसद नवाचारों को बढ़ावा देना और खास तरह के माल-ढुलाई वाले वैगन के डिजाइन में उद्योग जगत की भागीदारी को मुमकिन बनाना है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के तहत, वैगन के डिजाइन ज़्यादातर अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) द्वारा तैयार किए जाते थे, जिसमें बोगी, कपलर और ब्रेकिंग सिस्टम जैसे कई अहम पार्ट्स तय मानकों तक ही सीमित होते थे। इससे डिजाइन में बदलाव की गुंजाइश कम हो जाती थी और नई सोच या नवाचारों पर रोक लगती थी।

नई नीति के तहत, डिजाइनर, निर्माताओं और उद्योग खास तरह के सामान और ऑपरेशन की जरूरतों के हिसाब से वैगन के डिजाइन तैयार कर सकेंगे और उनके प्रस्ताव दे सकेंगे।

आरडीएसओ प्रस्तावित डिजाइन का मूल्यांकन करेगा और सैद्धांतिक मंजूरी मिलने पर प्रोटोटाइप बनाने की इजाजत देगा। विस्तृत डिजाइन, प्रोटोटाइप बनाने और कड़े स्थिर और गतिशील परीक्षण के बाद, पूरे रेक का फील्ड ट्रायल होगा। इसके बाद ही इसे सुरक्षा प्रमाणीकरण, मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण और सेवा में शामिल करने के लिए रेलवे बोर्ड की मंजूरी मिलेगी।

श्री वैष्णव ने कहा कि नए फ्रेमवर्क से स्टील, पेट्रोलियम, केमिकल, दूध, प्लास्टिक और दूसरे उद्योगों के लिए खास तरह के वैगन बनाने में आसानी होगी, जिन्हें स्वनिर्धारित परिवहन समाधान की जरूरत होती है। इस सुधार से वैगन डिजाइन और निर्माण के लिए एक नयी व्यवस्था बनने, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलने और अलग-अलग क्षेत्रों में माल ढुलाई की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।

पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन

श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंट (पीओएल) उत्पादों के परिवहन के लिए खास तरह के टैंक वैगन की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में, जिसमें सभी टैंक वैगन भारतीय रेलवे के पास होते थे, तेल कंपनियों को अपनी संचालन जरूरतों के हिसाब से खास वैगन लाने की आजादी नहीं थी।

इस समस्या को दूर करने के लिए, भारतीय रेलवे ने पेट्रोलियम टैंक वैगन के डिजाइन और उन्हें शामिल करने से जुड़ी संरचनात्मक रुकावटों को हटा दिया है। अब तेल कंपनियाँ सीधे खास वैगन खरीद सकेंगी या लीजिंग एजेंसियों के जरिए उन्हें लीज पर ले सकेंगी और खास जरूरतों के लिए भारतीय रेलवे नेटवर्क पर चला सकेंगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस सुधार से खास तरह के टैंक वैगन का इस्तेमाल शुरू हो सकेगा, रसद योजना बेहतर होगी, परिवहन का खर्च कम होगा, रेल से पेट्रोलियम उत्पादों की आवाजाही बढ़ेगी और उत्पाद का नुकसान और मिलावट जैसे सड़क परिवहन से जुड़े जोखिम भी कम होंगे।

अनाज, आटा और दालों का परिवहन

भारतीय रेलवे ने अनाज, आटा और दालों के परिवहन के लिए भी एक बड़ा सुधार किया है। इसके तहत माल ढुलाई के शुल्क को आसान बनाया गया है और कंटेनरों के जरिए ढुलाई को बढ़ावा दिया गया है।

नई नीति के तहत, पहले के मुश्किल स्लैब-आधारित माल ढुलाई ढांचे की जगह अब प्रति टन प्रति किलोमीटर की आसान दर वाला ढांचा लागू किया गया है। यह बदलाव कंटेनरों के जरिए अनाज, आटा और दालों के परिवहन की इजाजत देता है, जिससे इन्हें संभालना आसान हो जाता है, संग्रहण बेहतर होता है और संचालन की जरूरतों के हिसाब से अलग-अलग चरणों में इनका वितरण किया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कंटेनरों को विक्रेता या खरीददार के परिसर में रखा जा सकता है और पूरी रेक को रोके बिना, मांग के अनुसार इनका वितरण किया जा सकता है। चूंकि कंटेनर सील रहते हैं, इसलिए मिलावट या खराबी की संभावना भी काफी कम हो जाती है। इससे अनाज के परिवहन की सुरक्षा और गुणवत्ता बेहतर होती है और साथ ही लॉजिस्टिक्स की कार्यक्षमता भी बढ़ती है।

रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल के तहत, भारतीय रेलवे ने पहले नौ बड़े संरचनात्मक सुधार लागू किए थे, जिसमें ट्रेन के अंदर लगातार सफाई, गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों का विस्तार, रेलटेक पॉलिसी और पोर्टल, रेल दावा अधिकरण का डिजिटलीकरण, नमक और ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट के लिए खास कंटेनर, निर्माण-गुणवत्ता में सात सुधार, टिकट निरस्त करने और रिफंड के आसान नियम और बोर्डिंग पॉइंट में डिजिटल बदलाव शामिल हैं।

श्री वैष्णव ने कहा कि नए सुधारों से माल ढुलाई का एक बड़ा हिस्सा सड़क से रेल की ओर ले जाने में मदद मिलेगी, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और पर्यावरण को काफी फायदा होगा। उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन की तुलना में रेल परिवहन से लगभग 90 प्रतिशत कम कार्बन उत्सर्जन होता है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सामानों के लिए धीरे-धीरे कंटेनरों के इस्तेमाल को बढ़ाने से भारतीय रेलवे का माल ढुलाई का दायरा पारंपरिक थोक कार्गो से आगे बढ़ेगा और उसका माल ढुलाई का कारोबार और मजबूत होगा।

Scanned with OKEN Scanner

नई पहचान, नई सुविधाएं:

अमृत भारत स्टेशन योजना से बदल रहे देश के रेलवे स्टेशन

सूत्र - रे.स.ब्यू - अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के रेलवे स्टेशनों का तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत स्टेशन भवनों का पुनर्विकास, आधुनिक यात्री सुविधाओं का विस्तार, दिव्यांगजन-अनुकूल अवसंरचना, बेहतर सर्कुलेटिंग एरिया, डिजिटल सूचना प्रणाली और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले डिजाइनों को शामिल किया गया है। पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन न केवल यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करेंगे, बल्कि क्षेत्रीय रेल संपर्क, पर्यटन, व्यापार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति देंगे। आधुनिक अवसंरचना और स्थानीय पहचान के समन्वय के साथ ये स्टेशन भारतीय रेलवे के बदलते स्वरूप और भविष्य की यात्री-केंद्रित सोच को भी प्रतिबिंबित करते हैं।

आस्था और आधुनिकता का संगम बना पनकी धाम रेलवे स्टेशन

उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित पनकी धाम रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 25 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह स्टेशन अब यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और सुगम यात्रा अनुभव प्रदान कर रहा है। वर्ष 1981 में स्थापित इस स्टेशन का निर्माण कानपुर सेंट्रल पर बढ़ते यात्री दबाव को कम करने और शहर के पश्चिमी क्षेत्रों को बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। समय के साथ पंचमुखी श्री हनुमान मंदिर, पनकी धाम आने वाले श्रद्धालुओं और औद्योगिक गतिविधियों के कारण इसका महत्व लगातार बढ़ा। पुनर्विकास के तहत स्टेशन पर द्वि-मंजिला भवन, विशाल प्रतीक्षालय, एक्जीक्यूटिव लाउंज, रिटायरिंग रूम, आधुनिक टिकटिंग क्षेत्र, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर, उन्नत यात्री सूचना प्रणाली, बेहतर प्रकाश व्यवस्था और आधुनिक शौचालय जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। यात्रियों की आसान आवाजाही के लिए नए फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट, रैंप और सुव्यवस्थित सर्कुलेटिंग एरिया भी तैयार किया गया है।

स्टेशन की वास्तुकला में पनकी धाम की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान को भी प्रमुखता दी गई है। यह स्टेशन प्रसिद्ध पंचमुखी श्री हनुमान मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ स्थानीय उद्योग, व्यापार और पर्यटन को भी बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगा।

ऐतिहासिक फतेहपुर स्टेशन को मिला आधुनिक सुविधाओं का नया स्वरूप

दिल्ली हावड़ा मुख्य रेलमार्ग पर स्थित फतेहपुर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 32 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया गया है। ऐतिहासिक महत्व रखने वाला यह स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्र अनुभव प्रदान करेगा।

वर्ष 1859 से जुड़े इतिहास वाले इस स्टेशन का प्रयागराज और कानपुर के बीच महत्वपूर्ण स्थान है तथा यह लंबे समय से यात्रियों और व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। पुनर्विकास के तहत आकर्षक स्टेशन भवन, जी1 द्वितीय प्रवेश, विशाल कॉन्कोर्स, आधुनिक प्रतीक्षालय, उन्नत टिकटिंग व्यवस्था, विकसित सर्कुलेटिंग एरिया, सुव्यवस्थित पार्किंग और अलग प्रवेश-निकास मार्ग विकसित किए गए हैं।

यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्मों का आधुनिकीकरण, प्लेटफॉर्म संख्या-4 का उच्च स्तरीय निर्माण, नए शेल्टर, 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज, अतिरिक्त एफओबी, आधुनिक यात्री सूचना प्रणाली, बेहतर प्रकाश व्यवस्था तथा दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

पुनर्विकसित फतेहपुर रेलवे स्टेशन आधुनिक रेल अवसंरचना, बेहतर यात्री सुविधाओं और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह स्टेशन स्थानीय व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति प्रदान करेगा।

हरपालपुर रेलवे स्टेशन बना आधुनिक सुविधाओं और बेहतर कनेक्टिविटी का नया केंद्र

हरपालपुर रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 11.75 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह स्टेशन अब यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करेगा।

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हरपालपुर रेलवे स्टेशन झांसी मानिकपुर रेलखंड पर स्थित है और छतरपुर, टीकमगढ़, महोबा सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण रेल संपर्क केंद्र है। लंबे समय से यह स्टेशन क्षेत्र की कृषि, व्यापार, पर्यटन और दैनिक आवागमन की आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है। पुनर्विकास के तहत स्टेशन भवन का आधुनिकीकरण, आधुनिक बुकिंग हॉल, विशाल पोर्च, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, विकसित सर्कुलेटिंग एरिया, सुव्यवस्थित पार्किंग, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर, उन्नत प्रतीक्षालय, आधुनिक शौचालय तथा दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसके अलावा आधुनिक यात्री सूचना प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी, एलईडी प्रकाश व्यवस्था, कोच इंडिकेशन सिस्टम, मोबाइल चार्जिंग, पेयजल और अन्य आवश्यक यात्री सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया गया है। स्टेशन परिसर में स्थानीय कला और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाली चित्रकला के माध्यम से क्षेत्रीय पहचान को भी प्रमुखता दी गई है। आधुनिक अवसंरचना से लैस हरपालपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्रीय रेल संपर्क को मजबूत करने के साथ-साथ व्यापार, पर्यटन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति प्रदान करेगा।

बुंदेलखंड की विरासत के साथ आधुनिक बना महाराजा छत्रसाल छतरपुर स्टेशन

मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर छतरपुर स्थित महाराजा छत्रसाल रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत व्यापक पुनर्विकास किया गया है। लगभग 6.50 करोड़ की लागत से स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया है, जबकि यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए लगभग 10.27 करोड़ की लागत से 12 मीटर चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज भी बनाया गया है।

बुंदेलखंड क्षेत्र का यह महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन खजुराहो, पन्ना, ओरछा और आसपास के प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों तक पहुंच का प्रमुख केंद्र है। पुनर्विकास के तहत स्टेशन भवन का सौंदर्यीकरण, आधुनिक प्रवेश द्वार, विशाल प्रतीक्षालय, उन्नत शौचालय, बेहतर पेयजल व्यवस्था, विकसित सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग और आधुनिक प्लेटफॉर्म सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। स्टेशन पर आधुनिक यात्री सूचना प्रणाली, एलईडी प्रकाश व्यवस्था, कोच इंडिकेशन बोर्ड, मोबाइल चार्जिंग सुविधा, सीसीटीवी निगरानी, व्हीलचेयर, जन औषधि केंद्र और अन्य यात्री सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया गया है। दिव्यांगजन-अनुकूल रैंप, टैक्टाइल पाथ, विशेष शौचालय और सुगम आवागमन की व्यवस्थाएं स्टेशन को अधिक समावेशी बनाती हैं।

चंबल अंचल के भिण्ड स्टेशन को मिली आधुनिक रेल अवसंरचना की नई पहचान

भिण्ड रेलवे स्टेशन लगभग 11.79 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह स्टेशन अब यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करेगा।

उत्तर मध्य रेलवे का यह महत्वपूर्ण स्टेशन मध्य प्रदेश के भिण्ड जिले को देश के विभिन्न प्रमुख शहरों से जोड़ता है और क्षेत्र में दैनिक आवागमन, कृषि, व्यापार तथा सामाजिक गतिविधियों के लिए अहम भूमिका निभाता है। पुनर्विकास के तहत स्टेशन भवन का सौंदर्यीकरण, विकसित सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, लैंडस्केपिंग और आधुनिक यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 12 मीटर चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज, आधुनिक प्लेटफॉर्म शेल्टर, उन्नत प्रतीक्षालय, बेहतर पेयजल व्यवस्था, आधुनिक शौचालय, एलईडी प्रकाश व्यवस्था, डिजिटल यात्री सूचना प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी, मोबाइल चार्जिंग सुविधा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए लिफ्ट, रैंप, टैक्टाइल पाथ, व्हीलचेयर और अन्य सुगम सुविधाएं भी विकसित की गई हैं।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक स्वरूप में तैयार हुआ डीग रेलवे स्टेशन

डीग रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 15.24 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह स्टेशन अब यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करेगा।

पुनर्विकास के तहत स्टेशन भवन का नवीनीकरण, आकर्षक प्रवेश एवं निकास द्वार, आधुनिक प्लेटफॉर्म शेल्टर, उन्नत प्लेटफॉर्म सतह, बेहतर बैठने की व्यवस्था, आधुनिक प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय, विकसित सर्कुलेटिंग एरिया और सुव्यवस्थित पार्किंग का निर्माण किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए उन्नत सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली और अन्य आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाओं के तहत स्टेशन पर रैंप, टैक्टाइल पाथ, कम ऊंचाई वाले टिकट काउंटर, विशेष पेयजल व्यवस्था, व्हीलचेयर, लिफ्ट और समर्पित पार्किंग विकसित की गई है। वहीं, यात्रियों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही के लिए 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज भी बनाया गया है। आधुनिक अवसंरचना और उन्नत यात्री सुविधाओं से सुसज्जित डीग रेलवे स्टेशन क्षेत्रीय रेल संपर्क को मजबूत करने के साथ-साथ पर्यटन, व्यापार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति प्रदान करेगा।

धामपुर रेलवे स्टेशन नए कलेवर में तैयार, जल्द होगा लोकार्पण

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले स्थित धामपुर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास कार्य पूरा हो चुका है। आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित स्टेशन के लोकार्पण की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और इसकी आधिकारिक तिथि की घोषणा जल्द किए जाने की संभावना है।

पुनर्विकास के तहत स्टेशन भवन का आधुनिकीकरण, नए प्रतीक्षालय, आधुनिक शौचालय, बेहतर प्रकाश व्यवस्था और विस्तारित सर्कुलेटिंग एरिया विकसित किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए नए साइनेज, डिजिटल सूचना डिस्प्ले तथा दिव्यांगजन-अनुकूल रैंप और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

इसके अलावा स्टेशन परिसर में लैंडस्केपिंग और पौधारोपण के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल एवं आकर्षक वातावरण विकसित किया गया है। आधुनिक अवसंरचना और बेहतर यात्री सुविधाओं से सुसज्जित धामपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्रीय रेल संपर्क को मजबूत करने के साथ-साथ यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करेगा।

पर्यटन नगरी शिवपुरी को मिला आधुनिक रेलवे स्टेशन का नया उपहार

मध्य प्रदेश के शिवपुरी रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 22 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया गया है। आधुनिक सुविधाओं और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत के समन्वय के साथ विकसित यह स्टेशन अब यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करेगा।

पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाला शिवपुरी रेलवे स्टेशन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण रेल संपर्क और पर्यटन केंद्र है। पुनर्विकास के तहत स्टेशन भवन का आधुनिकीकरण, सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्यीकरण, प्लेटफॉर्म शेल्टर का विस्तार, नए प्रतीक्षालय, आधुनिक शौचालय, बेहतर बुकिंग काउंटर और आकर्षक स्टेशन परिसर विकसित किया गया है। यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए नया फुट ओवर ब्रिज भी बनाया गया है।

दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाओं के तहत स्टेशन पर रैंप, टैक्टाइल पाथ और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं। साथ ही बेहतर प्रकाश व्यवस्था और आधुनिक अवसंरचना से स्टेशन को अधिक सुरक्षित और आकर्षक बनाया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित शिवपुरी रेलवे स्टेशन क्षेत्रीय रेल संपर्क को मजबूत करने के साथ-साथ पर्यटन, स्थानीय विकास और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति प्रदान करेगा।

टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन बना आधुनिक सुविधाओं और विरासत का नया प्रतीक

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत व्यापक पुनर्विकास किया गया है। लगभग 6.50 करोड़ की लागत से स्टेशन भवन एवं यात्री सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया गया है, जबकि 13.50 करोड़ की लागत से 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज और 0.90 करोड़ की लागत से लिफ्ट सुविधा विकसित की गई है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह स्टेशन अब यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करेगा।

बुंदेलखंड क्षेत्र का महत्वपूर्ण टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन लंबे समय से क्षेत्र के यात्रियों, व्यापार, कृषि और पर्यटन के लिए अहम रेल संपर्क केंद्र रहा है। पुनर्विकास के तहत स्टेशन भवन का आकर्षक सौंदर्यीकरण, आधुनिक प्रतीक्षालय, स्वच्छ शौचालय, विकसित सर्कुलेटिंग एरिया, सुव्यवस्थित पार्किंग, उन्नत प्लेटफॉर्म, नए शेल्टर और बेहतर प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। स्थानीय स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए स्टेशन के स्वरूप को भी नया रूप दिया गया है।

यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक यात्री सूचना प्रणाली, एलईडी प्रकाश व्यवस्था, कोच इंडिकेशन बोर्ड, मोबाइल चार्जिंग सुविधा, पेयजल व्यवस्था, व्हीलचेयर, प्राथमिक उपचार और अन्य आवश्यक सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया गया है। वहीं, दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाओं के तहत रैंप, टैक्टाइल पाथ, लिफ्ट, विशेष शौचालय, लो-हाइट टिकट काउंटर और सुगम आवागमन की व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं।

दौसा रेलवे स्टेशन को मिला आधुनिक स्वरूप, यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

राजस्थान के दौसा रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 15 करोड़ की लागत से पुनर्विकास किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह स्टेशन अब यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करेगा।

दिल्ली अहमदाबाद रेलमार्ग पर स्थित दौसा रेलवे स्टेशन उत्तर पश्चिम रेलवे का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, जहां प्रतिदिन लगभग 15,000 यात्री आवागमन करते हैं। बढ़ती यात्री संख्या को देखते हुए स्टेशन भवन का नवीनीकरण, विकसित सर्कुलेटिंग एरिया, अलग प्रवेश एवं निकास द्वार, नया पोर्च और सुव्यवस्थित दोपहिया एवं चारपहिया पार्किंग का निर्माण किया गया है। स्टेशन भवन और प्रतीक्षालयों में स्थानीय कला, विरासत और संस्कृति को दर्शाने वाली कलाकृतियां भी विकसित की गई हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए लगभग 4.10 करोड़ की लागत से नया फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है, जिसमें रैंप और कवरिंग शेड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आधुनिक शौचालय, दो नई लिफ्ट, ट्रेन सूचना एवं कोच इंडिकेशन बोर्ड, सीसीटीवी निगरानी और अन्य आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। दिव्यांगजन-अनुकूल सुविधाओं के तहत हेल्प बूथ, रैंप, विशेष शौचालय, पेयजल सुविधा, पार्किंग और साइनेज की व्यवस्था भी की गई है।

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम सचिवालय में लेखपाल
शासन आपके द्वार

अब राजस्व सेवाएं होंगी और भी आसान, तेज एवं पारदर्शी!

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने से ग्रामीणों को अब राजस्व सेवाओं के लिए अनावश्यक भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी

मुख्य लाभ

- गांव में ही मिलेंगी राजस्व सेवाएं
  अब तहसील जाने की आवश्यकता कम
- जाति, आय, निवास, विरासत, खतौनी एवं
  अन्य राजस्व कार्यों का त्वरित निस्तारण
- ग्राम पंचायत और राजस्व विभाग के बीच बेहतर समन्वय
- जनसुनवाई एवं शिकायतों के शीघ्र समाधान की व्यवस्था
- सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग
- पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित राजस्व प्रशासन

ग्राम सचिवालय बनेगा
राजस्व सेवाओं का नया केंद्र - सरकार आपके और करीब

विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश UPGovtOfficial CMOUttarpradesh CMOfficeUP

Scanned with OKEN Scanner